

प्रेषक

प्रदीप सिंह रावत
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

मुख्य अभियंता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 20 अगस्त, 2007

विषय: अन्तर्राज्यीय संयोजन की योजना के अन्तर्गत (केन्द्र पोषित योजना) लक्सर-दल्लावाला मोटर मार्ग के किमी 0 16.00 से 30.00 तक सुधार/सुदृढीकरण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2286/17(बजट)/इन्दर स्टेट कनेक्टिविटी/2007-08 दिनांक 12.07.2007 के संदर्भ में सड़क पट्टिबन्धन एवं सड़क मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं 0 एन.एच.-17014/6/2005/यू.आर./एन.एच. 11 दिनांक 28.09.2005 के द्वारा स्वीकृत रु० 484.82 लाख की लागत के विपरीत शासनादेश सं 197/11(3)06-605(आई.एस.सी.) दिनांक 22.3.06 के द्वारा वर्ष 2005-06 में अवमुक्त रु० 50.00 लाख तथा शासनादेश सं 357/11(3)06-605(आई.एस.सी.)05 दिनांक 27.06.2006 तथा शासनादेश सं 23/11(3)07-605(आई.एस.सी.)05 दिनांक 20.03.2007 के द्वारा वर्ष 2006-07 में अवमुक्त रु० 300.00 लाख एवं शासनादेश सं 285/11(3)07-605(आई.एस.सी.)05 दिनांक 30.05.2007 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में अवमुक्त रुपये 45.00 लाख के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 हेतु अन्तर्राज्यीय संयोजन मद में प्राविधानित धनराशि रु० 89.82 लाख (रु० उन्मुख लाख बाराठ हजार मात्र) की धनराशि प्रश्नगत मार्ग के सुधार एवं सुदृढीकरण के लिए व्यय हेतु इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही किया जायेगा।

- उक्त कार्य तब तक आरम्भ न किया जाय और न इस पर कोई व्यय किया जाय और न ही इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का वित्तीय वायदा ही किया जाय जब तक कि प्रश्नगत कार्य के विस्तृत आगणन/नक्शे आदि पर सक्षम प्राधिकारी की दृष्टांतकीय/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।
- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उपरान्त प्रयुक्त की गयी कुल धनराशि का वर्षान्त भर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण भारत सरकार/शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- उक्त धनराशि का व्यय खरने से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्वज कला टेण्डर विषयक नियमों का या सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुस्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- व्यय उन्ही मदों/योजनाओं पर किया जायेगा जिनके विरुद्ध यह स्वीकृत किया जा रहा है और इस धनराशि को किसी अन्य योजना पर आवर्तन नहीं किया जायेगा ताकि भारत सरकार के लक्ष्य को अनुरूप ही वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हो सकें।
- कार्य की सम्यक्दृष्ट एवं गुणवत्ता का समस्त दायित्व सम्बन्धित अधिरासी अभियंता का ही होगा।
- उक्त कार्य करीब समय भारत सरकार द्वारा निर्गत संख्या एन.एच.-17014/6/2005/यू.आर./एन.एच.-11 दिनांक 28.9.2005 के एवं इसमें उल्लिखित अन्य समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। व्यय अनुमोदित दरों पर ही किया जायेगा, कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जायेगा और विलम्ब के कारण लागत

72/11114

- में वृद्धि के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियंता उत्तरदायी होंगे, धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जायेगा।
9. इस योजना पर कोई एजेंसी चार्ज देय नहीं होंगे।
 10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भी अविलम्ब प्रेषित करके अब तक राज्य सरकार के आय-व्यय में अवमुक्त धनराशि के विपरीत भारत सरकार से धनराशि की प्रतिपूर्ति करा कर उसका विवरण शासन को दे दिया जायेगा।
 11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय के अनुदान सख्या-22 के लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें- 04 इन्टरस्टेट कनेक्टिविटी योजना (100प्रतिशत केन्द्र पोषित)-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
 12. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के अ.संख्या 285/XXVII(2)/07 दिनांक 16 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

सख्या-474(1)/111(3)/07 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराखण्ड इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त कुमायू गण्डल नैनीताल।
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5. अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य मंत्री या मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
9. अधीक्षण अभियंता, 24वीं वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।